

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 71/2018

श्री किशनाराम पुत्र श्री श्योजी, जाति जाट, निवासी ग्राम अरवड़, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़

.....रेस्पोंडेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956

- उपस्थित :-
1. श्री भीयांराम चौधरी, वकील अपीलान्ट की ओर से।
 2. श्री हेमराज राठौड़, सरकारी वकील

:- आदेश :-

दिनांक -31.10.2019

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि सम्वत् 2075 में श्री किशनाराम पुत्र श्री श्योजी, जाति जाट, निवासी ग्राम अरवड़, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ने ग्राम अरवड़ के सिवायचक किस्म चा0 3 नाडी आराजी खसरा नम्बर 41 रकबा 0.24 हैक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूप से बाड़ व चारदीवारी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार सरवाड़ के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 11/2018 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 11.04.2018 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। इसके अतिरिक्त उन्हे पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर 3 माह के साधारण कारावास की सजा से भी दण्डित किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 11.04.2018 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। मियाद के बिन्दु पर पैरोकार सरकार द्वारा ऐतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर अपील गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित




अपर कलक्टर,
अजमेर

होकर विवादित भूमि पर से अपना अनाधिकृत रूप से किया गया अतिक्रमण हटा लेने का निवेदन कर दिया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये तथा कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया है जो निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्त ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि वर्तमान में विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है। न्याय का सुरथापित सिद्धांत है कि जब अतिक्रमियों द्वारा अपना कब्जा हटा लिया हो तो सिविल कारावास की सजा के आदेश को न्यायहित में निरस्त किया जाना चाहिये। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान R.R.T. 2009(2) पेज 858 व R.R.T. 2008(1) पेज 479 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि अपीलान्त द्वारा न्यायालय के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र कि उन्होंने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में किसी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करेगा, प्रस्तुत कर दिया जायेगा। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर सिविल कारावास की सजा माफ की जावे।

विद्वान वकील अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्त द्वारा अनाधिकृत रूप से सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है एवं विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में चा0 3 दर्ज है। इस तथ्य को अपीलान्त ने स्वयं स्वीकार किया है। अपीलान्त ने विवादित भूमि से कब्जा छोड़ने सम्बन्धी शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपीलान्त द्वारा विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया जाना प्रतीत नहीं होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्त द्वारा विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। जिस दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायिक आधार मेरे समक्ष नहीं है। अतः दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है। जहां तक 3 माह के कारावास की सजा में नरमी का रूख अपनाये जाने का प्रश्न है, अपीलान्त की ओर से इस अपील के साथ कब्जा नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है, उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्त सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।



(कैलाश चन्द्र शर्मा)
(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलेक्टर, अजमेर
अपर जिला कलेक्टर, अजमेर